आशापुरा माइन–केम लिमिटेड

बनाम

गुजरात खनिज विकास निगम

(2015 की सिविल अपील संख्या 3702)

16 अप्रैल, 2015

[न्यायमूर्ति फ़क्किर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 11, 16(1)(ए)––मध्यस्थता खंड––का आह्वान—धारा 16(1)(ए) एक वैध मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को मानती है और इसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में मानने का आदेश देती है—धारा 16(1)(बी) के आधार पर, मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य बना हुआ है, इस घोषणा के बावजूद कि अनुबंध अशक्त और शून्य था– मुख्य अनुबंध और मध्यस्थता समझौता दो स्वतंत्र अनुबंध बनाते है– मौजूदा मामले में, सवाल या इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या एमओयू किसी भी शर्त को पूरा न करने या किसी भी पक्ष द्वारा एमओयू के अन्य खंडों में किसी भी आवश्यकता के अनुपालन में विफलता को ध्यान में रखते हुए एक पूर्ण समझौते में परिणत हुआ है, पक्षों के बीच ऐसे विवादों को आम सहमति से एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजने के लिए अपीलकर्ता और प्रतिवादी द्वारा विशिष्ट समझौता किया गया था– इसलिए, जब संदर्भ देने के लिए पक्षों के बीच आम सहमति नहीं बनी, तो अधिनियम की धारा 11 को लागू करने और मध्यस्थता के लिए विवाद का संदर्भ लेने के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक के लिए यह खुला था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. खंड 27 के अनुसार, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद या मतभेद से संबंधित द्विपक्षीय स्तर पर सौहार्दपूर्ण समाधान की विफलता की स्थिति में, जैसा कि एमओयू के खंड 26 में निहित है, ऐसे अनसुलझे विवाद या मतभेद से संबंधित या एमओयू से उत्पन्न होने वाले, इसके कार्यान्वयन के उल्लंघन या समाप्ति, जिसमें एमओयू की किसी भी शर्त की व्याख्या के बारे में कोई मतभेद या विवाद शामिल है, अपीलकर्ता और प्रतिवादी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जा सकता है। इसलिए, जब संदर्भ देने के लिए पक्षों के बीच आम सहमति नहीं बनी, तो अंततः अधिनियम की धारा 11 को लागू करने और मध्यस्थता के लिए विवाद का संदर्भ लेने के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक के लिए खुला होगा। मौजूदा मामले में, एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रतिवादी के निदेशक मंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें शर्तों में संशोधन के अधीन, एमओयू के लिए अपनी मंजूरी व्यक्त की गई। इसके बाद 17.12.2007 से 10.03.2010 तक पक्षों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान हुआ। 18.03.2010 को प्रतिवादी का एक अनुवर्ती बोर्ड प्रस्ताव था जिसमें कहा गया था कि बोर्ड ने निर्णय लिया कि वह राज्य सरकार की खनिज नीति में बदलाव के कारण प्रस्तावित एमओयू की वैधता को बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। हालाँकि, 26.07.2010 को, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि समानता बनाए रखने के लिए, एमओयू के नियमों और शर्तों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को सूचित किया गया था, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी और उसके प्राप्त होने पर ऐसी मंजूरी से एक नया एमओयू निष्पादित किया जा सकता है। इसके बाद, दिनांक 25.4.2011 को संचार द्वारा, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि उसने एमओयू के विभिन्न नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता के संबंध में अपीलकर्ता की ओर से गलती का आरोप लगाते हुए एमओयू को तुरंत रद्द करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, घटनाओं के अनुक्रम से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों पक्ष एमओयू में निहित विभिन्न नियमों और शर्तों के संदर्भ में भिन्न थे और

परिणामस्वरूप, जैसा कि एमओयू के खंड 26 में निर्दिष्ट है, पहली बार में सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश करने का दोनों पक्षों में से प्रत्येक को पूरा अधिकार था। [पैरा 30,31] [899-ए-एच; 900-ए-डी]

2. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से पता चला कि अपीलकर्ता ने द्विपक्षीय स्तर पर विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की इच्छा व्यक्त की। चूंकि प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, अपीलकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एमओयू के खंड 27 को लागू करके कानूनी नोटिस भेजा और एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम भी सुझाया और प्रतिवादी की सहमति मांगी। प्रतिवादी ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया कि वह संदर्भ के लिए सहमत होने के लिए इच्छुक नहीं है, अपीलकर्ता के पास अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय का रुख करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसलिए, खंड 27 एमओयू में निहित एक वैध मध्यस्थता समझौता है, और अपीलकर्ता उक्त समझौते को लागू करने और मध्यस्थ के संदर्भ की तलाश करने का पूरी तरह से हकदार था। निष्कर्ष के मद्देनजर, चूंकि प्रतिवादी ने अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की है और इस तरह पक्ष सहमत प्रक्रिया के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहे, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है। [पैरा 32, 33, 34] [900-ई-एच; 901-ए-बी, डी-ई]

एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम एनरकॉन जीएमबीएच और अन्य 2014 (5) एससीसी 1: 2014 (2) एससीआर 855; रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम ग्रीन मोबाइल 2012 (2) एससीसी 93: 2011 (13) एससीआर 359; टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और अन्य 2014 (5) एससीसी 68: 2013 (3) एससीआर 589––पर भरोसा किया गया।

एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य 2005 (8) एससीसी 618: 2005 (4) पूरक एससीआर 688; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 2009 (1) एससीसी 267: 2008 (13) एससीआर 638; क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन और अन्य 2013 (1) एससीसी 641: 2012 (13) एससीआर 402 – संदर्भित किए गये।

निर्णय विधि संदर्भ

2014 (2) एससीआर 855	भरोसा किया गया	पैरा 16
2011 (13) एससीआर 359	भरोसा किया गया	पैरा 16
2013 (3) एससीआर 589	भरोसा किया गया	पैरा 16
2005 (4) पूरक एससीआर 688	संदर्भित किया गया	पैरा 16
2008 (13) एससीआर 638	संदर्भित किया गया	पैरा 16
2012 (13) एससीआर 402	संदर्भित किया गया	पैरा 16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की सिविल अपील सं 3702

मध्यस्थता अधिनियम के तहत 2013 की याचिका संख्या 9 में अहमदाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांक 27.09.2013/04.10.2013 के निर्णय और आदेश से।

दुष्यंत दवे, सत्येन थाकुर, पारुल शुक्ला, प्रत्यूष पंजवानी, महेश अग्रवाल, ई.सी. अग्रावला, अंकुर सैगल अपीलार्थी के लिए।

विकास सिंह, संजय कपूर, अनमोल चंदन, दीपिका कालिया प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति फ़क्किर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला द्वारा दिया गया

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील मध्यस्थता याचिका संख्या 9/2013 में अहमदाबाद में गुजरात के उच्च न्यायालय के दिनांक 27.9.13/04.10.2013 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 11 के तहत दायर अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया।

3. जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है, वे यह हैं कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने 17.08.2007 को एक समझौते के ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। उक्त एमओयू के तहत, अपीलकर्ता ने चीनी कंपनी, अर्थात् "मैसर्स किंग टोंगज़िया एल्युमीनियम ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन की निंगज़िया (इसके बाद "क्यूटीएक्स" के रूप में संदर्भित) के साथ-साथ प्रतिवादी के साथ गुजरात के कच्छ जिले में उपयुक्त क्षमता का एक एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के लिए एक संयुक्त उद्यम गठित करने का प्रस्ताव रखा। एमओयू में यह भी दर्ज है कि गुजरात सरकार एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए सहमत हुई है। प्रतिवादी कच्छ जिले में अपने 10 मौजूदा और 18 अपेक्षित बॉक्साइट खनन पट्टों से प्रस्तावित संयंत्र को प्राथमिकता के आधार पर मध्यम ग्रेड बॉक्साइट की आपूर्ति करने पर सहमत हुआ।

4. अन्य प्रासंगिक शर्तें यह थीं कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में क्यूटीएक्स की इक्विटी भागीदारी की व्यवस्था करनी चाहिए, यह की प्रतिवादी को संयुक्त उद्यम की इक्विटी में गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक निवेश करना चाहिए, लेकिन 26% से अधिक नहीं। अपीलकर्ता और क्यूटीएक्स के पास 74% इक्विटी होनी चाहिए। प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता 1.00 मिलियन टन प्रति वर्ष होनी चाहिए जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। प्रतिवादी की ओर से, उसे परियोजना स्थापित करने

के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करने में संयुक्त उद्यम की सहायता करनी चाहिए। खंड 5, 6, 8, 10 और 11 के तहत, प्रतिवादी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मध्यम ग्रेड बॉक्साइट की मात्रा, बॉक्साइट का ग्रेड, विनिर्देश, वह दर जिस पर इसकी आपूर्ति की जानी थी, वह समय जिसके भीतर ऐसी आपूर्ति को प्रभावी किया जाना चाहिए, यह सब निर्धारित किया गया था जिसमें आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौता भी शामिल था।

5. एमओयू में कुछ अन्य शर्तें भी निर्धारित की गईं, जिसके तहत अपीलकर्ता को एमओयू पर हस्ताक्षर करने के 60 दिनों के भीतर प्रतिवादी को 3.94 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य किया गया, जो प्रतिवादी द्वारा उसके एल्यूमिना प्रोजेक्ट और संबंधित मामले पर किए गए प्रत्यक्ष खर्च थे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलकर्ता ने उक्त राशि का चेक दिया लेकिन प्रतिवादी ने उसे नहीं भुनाया। इसमें अपीलकर्ता को हस्ताक्षर बोनस के रूप में एमओयू के निष्पादन के 60 दिनों के भीतर प्रतिवादी को 6.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के अलावा संयुक्त उद्यम के उचित पालन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर एमओयू के विभिन्न नियमों और शर्तों के तहत अपीलकर्ता द्वारा 10 करोड़ रुपये के मूल्य की बैंक गारंटी प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया।

6. एमओयू के खंड 12 में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि अधिकार और विशेषाधिकार पांच साल की अवधि के लिए हस्तांतरणीय नहीं थे और अपीलकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद पांच साल की अवधि के लिए परियोजना/संयुक्त उद्यम से बाहर नहीं निकलना चाहिए।

7. खंड 19 के तहत, यह निर्धारित किया गया था कि एमओयू अपीलकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन था, प्रतिवादी के इक्विटी निवेश और निर्णय गुजरात सरकार की सहमति के अधीन होने चाहिए, जबकि

अपीलकर्ता का निवेश उसके शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होना चाहिए। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों को एमओयू के निष्पादन की तारीख से तीन महीने के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आगे यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि दोनों पक्षों द्वारा आवश्यक अनुमोदन मिलने पर, एमओयू को अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच एक समझौते में बदल दिया जाएगा। खंड 21 में इस आशय की प्रासंगिक शर्त शामिल थी कि यदि एमओयू पर हस्ताक्षर करने के छह महीने के भीतर परियोजना में इक्विटी भागीदारी के लिए गुजरात सरकार की सहमति नहीं मिलती है, तो एमओयू को प्रतिवादी द्वारा अपनी कच्छ की खदानों से संयुक्त उद्यम के लिए मध्यम श्रेणी का बॉक्साइट की दीर्घकालिक आपूर्ति से संबंधित माना जाएगा।

8. मध्यस्थता से संबंधित एमओयू में निहित अधिक महत्वपूर्ण खंड, खंड 26 और 27 में पाए जाते हैं जो निम्नानुसार हैं:

> "26. इस एमओयू से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में, इस तरह के विवाद/मतभेद को, पहली बार में, किसी भी पक्ष द्वारा विवाद के संदर्भ के 45 दिनों के भीतर आपसी परामर्श से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा।
>
> 27. यदि पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो पाता है तो एमओयू और इसके कार्यान्वयन से संबंधित या उत्पन्न होने वाले ऐसे अनसुलझे विवाद या मतभेद, उल्लंघन या समाप्ति, जिसमें एमओयू की किसी भी शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई मतभेद या विवाद शामिल है को मध्यस्थता या जीएमडीसी और एएमएल में नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थ तर्कसंगत निर्णय देगा। मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (भारत)

द्वारा शासित होगी और अहमदाबाद शहर में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी. पक्ष मध्यस्थता की लागत को समान रूप से साझा करेंगे। मध्यस्थता खंड वित्तीय स्रोतों को स्वीकार्य होगा।"

9. उपरोक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रतिवादी का दिनांक 29.10.2007 का एक बोर्ड प्रस्ताव था। उक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि बोर्ड ने अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच 17.08.2007 को निष्पादित एमओयू को उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित संशोधनों के अधीन अपनी मंजूरी देने का संकल्प लिया है। अपीलकर्ता को सूचित किए गए उक्त प्रस्ताव के बाद, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच और कुछ अवसरों पर 17.12.2007 और 10.03.2010 के बीच गुजरात राज्य के प्रधान सचिव के साथ पत्राचार का आदान-प्रदान किया गया। प्रतिवादी का दिनांक 18.03.2010 का एक बोर्ड प्रस्ताव था जो बताता है कि बोर्ड ने इस आशय का निर्णय लिया कि नवंबर, 2009 में राज्य सरकार द्वारा घोषित नई खनिज नीति के आलोक में, बॉक्साइट के संबंध में भी बड़े बदलाव किए गए थे और इसलिए, वह प्रस्तावित एमओयू की वैधता को बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं था और एल्यूमिना में उच्च मूल्यवर्धन के लिए बॉक्साइट में नए ईओआई को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया। हालाँकि, दिनांक 26.07.2010 के बाद के संचार में, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि समानता बनाए रखने के लिए दिनांक 17.8.2007 के एमओयू के नियमों और शर्तों में आवश्यक संशोधन, जैसा कि प्रतिवादी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को सूचित किया गया था, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही था और ऐसी मंजूरी मिलने पर एक नया एमओयू निष्पादित करना पड़ सकता है।

10. लेकिन बाद में, दिनांक 25.04.2011 को संप्रेषण द्वारा, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को चुपचाप सूचित किया कि उसने एमओयू के विभिन्न नियमों और शर्तों के अनुपालन में अपीलकर्ता की ओर से विफलता के मद्देनजर 17.08.2007 के एमओयू

को तुरंत रद्द करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, प्रतिवादी ने प्रस्तावित परियोजना को अंतिम रूप नहीं दे पाने के लिए अपीलकर्ता पर दोष मढ़ दिया।

11. उक्त पत्र दिनांक 25.04.2011 के जवाब में, अपीलकर्ता ने 11.07.2011 को एक विस्तृत उत्तर लिखा जिसमें अपीलकर्ता ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की इच्छा व्यक्त की और प्रतिवादी से अनुरोध किया कि वह प्रतिवादी के दिनांक 25.04.2011 के पत्र में उल्लिखित मुद्दों और कथित उल्लंघनों के संबंध में एक सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रयास करे। इसके बाद, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को दिनांक 07.12.2012 को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें यह दावा किया गया कि एमओयू के खंड 26 के तहत प्रदान किए गए विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का उसका प्रयास विफल रहा और, इसलिए, उसने एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए एमओयू के खंड 27 को लागू करने का निर्णय लिया और प्रतिवादी की सहमति से नियुक्ति के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नाम का सुझाव दिया या फिर अधिनियम की धारा 11 को लागू करने के अपीलकर्ता के निर्णय का सुझाव दिया।

12. प्रतिवादी की ओर से, 04.01.2013 को अपीलकर्ता को एक उत्तर दिया गया जिसमें कहा गया कि उसकी ओर से कोई भी गलती नहीं थी और इसलिए, उसकी ओर से किसी भी दायित्व को पूरा करने का कोई सवाल ही नहीं था और उसने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति न देने का अपना निर्णय भी व्यक्त किया।

13. घटनाओं के उपर्युक्त अनुक्रम में यानी एमओयू की तारीख से आवेदन दाखिल करने की तारीख तक, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की। आक्षेपित आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज किये जाने पर, अपीलकर्ता इस अपील के साथ आगे आया है।

14. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यन्त दवे और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह को सुना। श्री दुष्यन्त दवे ने दिनांक 17.8.2007 के एमओयू से लेकर उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता आवेदन की अस्वीकृति तक अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच हुई उपरोक्त घटनाओं का उल्लेख करने के बाद तर्क दिया कि चूंकि निर्विवाद रूप से प्रतिवादी ने एमओयू समाप्त कर दिया, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि यह मृत था, पूरी तरह से अनुचित था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के लिए एमओयू अंततः संयुक्त उद्यम के निर्माण में सफल नहीं हुआ, लेकिन एमओयू के खंड 26 और 27 उनमें निहित विशिष्ट शर्तों के आधार पर मध्यस्थता और उक्त सहमत शर्तों के संदर्भ में स्टैन्ड-अलोन समझौते के रूप में काम करेंगे, चूंकि पक्षों के बीच एक आम सहमति थी, उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थ नियुक्त करना चाहिए था, क्योंकि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता द्वारा सुझाया गए नामित मध्यस्थ के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने से इनकार कर दिया था।

15. उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय इस बात को उजागर करने में सक्षम था कि पक्षों के पास स्वयं एमओयू के संदर्भ में भी कोई आम सहमति नहीं थी और इन परिस्थितियों में, जैसा कि अपीलकर्ता ने दावा किया है, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए खंड 26 और 27 को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

16. जहां विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम एनरकॉन जीएमबीएच और अन्य — 2014 (5) एससीसी 1, रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम ग्रीन मोबिल – 2012 (2) एससीसी 93 और टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और अन्य – 2014 (5) एससीसी 68 के फैसलों पर भरोसा जताया, श्री विकास सिंह ने अपने

प्रस्तुतीकरण के समर्थन में एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य – 2005 (8) एससीसी 618, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड – 2009 (1) एससीसी 267 और क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरिफिकेशन इंक और अन्य – 2013 (1) एससीसी 641 के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर भरोसा किया।

17. संबंधित वकील की दलीलों को सुनने के बाद, हमने पाया कि श्री दुष्यंत दवे की दलील का निष्कर्ष और सार यह था कि एमओयू के खंड 27 में निहित मध्यस्थता खंड एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता था और इसलिए, भले ही प्रतिवादी ने दिनांक 17.8.2007 के एमओयू को समाप्त करने का निर्णय लिया हो, मध्यस्थता समझौता बना रहेगा और परिणामस्वरूप पार्टियां उक्त खंड 27 को लागू करने और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपने विकल्प का उपयोग करने और दूसरे पक्ष की सहमति लेने की हकदार हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी ने एमओयू को समाप्त करने का अपना निर्णय व्यक्त किया था, इसलिए अपीलकर्ता ने अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच खंड 26 को लागू करके द्विपक्षीय स्तर पर सौहार्दपूर्ण समाधान के अपने प्रयास समाप्त करने के बाद, प्रतिवादी द्वारा खंड 27 को उपयोग में लेने पर खंड 27 को लागू करने और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति बी.एन. मेहता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का विकल्प चुनने और प्रतिवादी की सहमति मांगने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि जब प्रतिवादी ने उक्त विद्वान न्यायाधीश की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति से सहमत होने से इनकार कर दिया, तो अपीलकर्ता द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित था। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर उक्त आवेदन की अस्वीकृति निरस्त किये जाने योग्य है और एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिए।

18. प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह के अनुसार चूंकि एमओयू स्वयं एक संपन्न अनुबंध नहीं था, इसलिए उक्त एमओयू के खंड 26 और 27 जीवित नहीं रहते और परिणामस्वरूप एमओयू के खंड 27 को लागू करके मध्यस्थ की नियुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं थी।

19. संबंधित तर्कों की सराहना करने के लिए और इस मुद्दे पर कानून को पहले से ही एक से अधिक निर्णयों में तय किए जाने के संबंध में, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के उक्त प्रस्ताव के अनुरूप अपना निर्णय देने के लिए इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के बयान को सीधे देखा जा सकता है।

20. इस संदर्भ में, हम पाते हैं, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे द्वारा रेवा इलेक्ट्रिकल कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर), टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (ऊपर) और एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) के जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया वे अपीलकर्ता के रुख का पूरा समर्थन करते हैं। रेवा इलेक्ट्रिकल कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय एक मामला था जो अधिनियम की धारा 11 के तहत उत्पन्न हुआ था। उक्त मामले में प्रतिवादी की ओर से इस आशय का प्रश्न उठाया गया था कि एमओयू के समाप्त होने के साथ ही मध्यस्थता खंड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उक्त प्रश्न से निपटते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने पैराग्राफ 54 और 55 में निम्नानुसार कहा है:

> "54. धारा 16(1) के तहत, विधायिका यह स्पष्ट करती है कि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर विचार करते समय, मध्यस्थता खंड जो अनुबंध का हिस्सा बना, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलतफहमी न हो, धारा 16(1)(बी) में आगे प्रावधान है कि भले ही मध्यस्थ

न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि अनुबंध अशक्त और शून्य है, कानून के मामले में, इसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता खंड स्वत: अमान्य नहीं होना चाहिए। धारा 16(1)(ए) एक वैध मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को मानती है और इसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में मानने का आदेश देती है। धारा 16(1)(बी) के आधार पर, अनुबंध के अमान्य होने की घोषणा के बावजूद यह प्रवर्तनीय बना हुआ है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 16(1) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, सुश्री अहमदी की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं होगा कि 31-12-2007 को एमओयू की समाप्ति के साथ, मध्यस्थता खंड अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।

55. जैसा कि पहले देखा गया है, पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद स्पष्ट रूप से पक्षों के बीच संबंधों की विषय-वस्तु से संबंधित हैं जो एमओयू के माध्यम से अस्तित्व में आए हैं। इसलिए, स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने की आवश्यकता है। मध्यस्थता खंड के तहत, एक संदर्भ दिया जाना था कि विवादों को एक ही मध्यस्थ के पास भेजा जाना था। चूंकि पार्टियां सहमत प्रक्रिया के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रही हैं, इसलिए इस न्यायालय के लिए मध्यस्थ नियुक्त करना आवश्यक है।" (जोर दिया गया)

21. इन टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय ने रेवा इलेक्ट्रिकल कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा बताए गए कानून के बयान को मंजूरी दे दी। अनुच्छेद 14 को उपयोगी रूप से संदर्भित किया जा सकता है जो इस प्रकार है:

"14. रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम ग्रीन मोबिल का फैसला करते समय इस बेंच के एक सदस्य (एस.एस. निज्जर, जे.) ने भी यही तर्क अपनाया था, जिसमें धारा 16(1) के प्रावधान कॉम्पेटेंज़ कॉम्पेटेंज़ के सिद्धांत की पृष्ठभूमि पर विचार किया गया और अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि धारा 16(1) के तहत, विधायिका यह स्पष्ट करती है कि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर विचार करते समय, मध्यस्थता खंड, जो अनुबंध का हिस्सा बनने के बाद इसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाना था। उक्त निर्णय में 1996 अधिनियम की धारा 16(1)(बी) के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया था, जो यह प्रावधान करता है कि भले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि अनुबंध अशक्त और शून्य है, कानून के अनुसार, इसका परिणाम मध्यस्थता खंड के स्वचालित अमान्यकरण में नहीं होना चाहिए। यह भी माना गया कि 1996 अधिनियम की धारा 16(1)(ए) एक वैध मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को मानती है और इसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाना अनिवार्य करती है। 1996 अधिनियम की धारा 16(1)(बी) के आधार पर, मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य बना हुआ है, इस घोषणा के बावजूद कि अनुबंध अशक्त और शून्य था।" (जोर दिया गया)

22. फिर से यही प्रश्न एनरकोन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) में विचार के लिए आया, जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति एफ.एम.आई. कलीफुल्ला) एक पक्ष थे। उक्त निर्णय में, पक्षों के बीच लेनदेन की प्रकृति कमोबेश इस मामले के तथ्यों के समान थी। उस मामले में अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया तर्क यह था कि संपन्न अनुबंध के अभाव में कोई मध्यस्थता समझौता नहीं हो सकता है, इसलिए, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व में आने का कोई सवाल ही नहीं था और इसलिए, विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।

23. उपरोक्त प्रस्तुतियों के विपरीत, उक्त निर्णय में प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि भले ही मुख्य अनुबंध का अस्तित्व विवाद में है, न्यायालय का संबंध केवल मध्यस्थता समझौते से है, यानी मध्यस्थता खंड और जब एक बार ऐसा खंड मौजूद होता है, तो इसके परिणामस्वरूप मामला स्वयं मध्यस्थता के लिए संदर्भित हो जाएगा। दरअसल, उक्त मामले में मध्यस्थता से संबंधित खंड, खंड संख्या 18.1 में पाया गया था, जिसमें तकरार, विवाद या मतभेद को आपसी परामर्श के माध्यम से हल करने का प्रयास करने का प्रावधान था और यदि चर्चा शुरू होने के 30 दिनों के भीतर आपसी परामर्श से इसका समाधान नहीं होता है, तो पक्ष समाधान के लिए तकरार, विवाद या मतभेद को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास भेज सकते हैं।

24. उक्त खंड और संबंधित पक्षों की ओर से उठाए गए तर्कों से निपटते हुए, कानून को पैराग्राफ 82 और 83 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

> "82. इसके अलावा, आईपीएलए के खंड 18.1 से 18.3 में निहित मध्यस्थता समझौता बहुत व्यापक रूप से लिखा गया है और इसमें पक्षों के बीच कानूनी संबंधों से संबंधित सभी तकरार, विवाद या मतभेद शामिल होंगे। इसमें आईपीएलए की वैधता, व्याख्या, निर्माण, प्रदर्शन, प्रवर्तन या इसके कथित उल्लंघन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद शामिल होंगे। <u>मध्यस्थता समझौते और/या मध्यस्थता खंड की व्याख्या करते समय, न्यायालय को भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले मामलों में न्यायालयों या न्यायिक अधिकारियों द्वारा कम से कम हस्तक्षेप की व्यापक नीति के प्रति सचेत रहना चाहिए</u>। उपरोक्त के मद्देनजर, हमारे लिए श्री नरीमन की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि मध्यस्थता समझौता ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आईपीएलए को अंतिम रूप नहीं

दिया गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मध्यस्थता खंड (समझौता) अंतर्निहित अनुबंध यानी मध्यस्थता खंड वाले आईपीएलए से स्वतंत्र है। धारा 16 में प्रावधान है कि किसी अनुबंध का हिस्सा बनने वाले मध्यस्थता खंड को ऐसे अनुबंध से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाएगा।

83. अंतर्निहित अनुबंध से मध्यस्थता खंड/समझौते को अलग करने की अवधारणा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मध्यस्थता द्वारा विवादों को सुलझाने की पक्षों की मंशा वैधता, मान्यता, अंतिमता या अंतर्निहित अनुबंध के उल्लंघन की हर चुनौती के साथ हवा में उड़ न जाए। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996, जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 16 के तहत इस अवधारणा को स्वीकार करता है कि मुख्य अनुबंध और मध्यस्थता समझौता दो स्वतंत्र अनुबंध बनाते हैं। वाणिज्यिक अधिकार और दायित्व अंतर्निहित, मूल या मुख्य अनुबंध में निहित हैं। इसके बाद दूसरा अनुबंध होता है, जो मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्निहित अनुबंध से संबंधित विवादों को हल करने के लिए पक्षों के समझौते और इरादे को व्यक्त करता है। सामान्य सिविल न्यायालय उपाय के बाहर एक उपाय का चुनाव पक्षों द्वारा किया जाता है। यह सच है कि मध्यस्थता की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अदालतों के समर्थन की आवश्यकता होगी, लेकिन इससे संपार्श्विक मध्यस्थता समझौते की वैधता या स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आएगी, भले ही यह एक अनुबंध में निहित हो, जिसका पक्षों में से किसी एक द्वारा शून्य या शून्यकरणीय या अनिर्धारित होने का दावा किया जाता है।"

(जोर दिया गया)

25. प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला देते हुए यह तर्क देने की कोशिश की कि टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में उक्त निर्णय के पैराग्राफ 13 में बताई गई स्थिति के विशेष संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पर निर्भरता उचित नहीं थी।

26. हम उक्त निवेदन पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि हमने पाया है कि हमें उक्त मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है कि टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) के फैसले के पैराग्राफ 13 में जो कहा गया था वह सही था या नहीं, जब यह पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (ऊपर) में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ देता है। हम केवल इस सवाल से संबंधित हैं कि क्या एमओयू में शामिल मध्यस्थता खंड एक स्टैन्ड-अलोन समझौता है या नहीं। उस उद्देश्य के लिए, टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में पैराग्राफ 14 में जो कहा गया है वह केवल प्रासंगिक है और हम उसमें बताई गई कानूनी स्थिति को इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में लगातार निर्धारित अनुपात निर्णय के अनुरूप पाते हैं।

27. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के निर्णय पर भी निर्भरता रखी गई थी। उक्त निर्णय में पैराग्राफ 19, 20 और 21 का उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद 19 को उपयोगी रूप से संदर्भित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

> "19. एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में, इस न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम की धारा 11 के दायरे पर विचार किया और माना कि अधिनियम की धारा 11 की योजना के लिए मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को यह निर्णय लेने की आवश्यकता है कि क्या अधिनियम की धारा 11(6) और इसके निहितार्थों के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले

अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में एक मध्यस्थता समझौता है। यह विचार था कि नए अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (4), (5) और (6) पुराने अधिनियम (मध्यस्थता अधिनियम, 1940) की धारा 8 और 20 के तहत न्यायालय में निहित शक्ति को जोड़ती है। इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 660-61 और 663, पैरा 39 और 47)

"39. यह परिभाषित करना आवश्यक है कि मुख्य न्यायाधीश ने वास्तव में क्या रुख अपनाया अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन के साथ, ये उस स्तर पर निर्णय लेना है। जाहिर है, उन्हें इस अर्थ में अपना क्षेत्राधिकार तय करना होगा, चाहे पक्ष बनाने वाला हो प्रस्ताव ने सही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उसे यह तय करना होगा कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता है, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है और क्या जिस व्यक्ति ने उसके समक्ष अनुरोध किया है, वह ऐसे समझौते में एक पक्ष है। यह इंगित करना आवश्यक है कि वह इस प्रश्न का निर्णय भी कर सकता है कि क्या दावा मृत था; या लंबे समय से अटका हुआ दावा जिसे पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी और क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके लेनदेन पूरा किया है। उस स्तर पर यह तय करना संभव नहीं हो सकता है कि किया गया दावा मध्यस्थता खंड के दायरे में आता है या नहीं। उस प्रश्न को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य लेने के साथ-साथ मध्यस्थता में शामिल दावों के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए छोड़ देना उचित होगा। मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना होगा कि आवेदक ने धारा

11(6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शर्तों को पूरा किया है या नहीं। इन निष्कर्षों पर निर्णय लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश या तो अर्धनामों और पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं या ऐसे विशिष्ट चिह्न ले सकते हैं या ऐसे विशिष्ट चिह्न प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी आवश्यकता हो। हमारा मानना है कि अधिनियम के संदर्भ में इस प्रक्रिया को अपनाने से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के विभिन्न चरणों में न्यायालय में बहुत अधिक संपर्क किए बिना, मध्यस्थता की प्रक्रिया में तेजी लाने के अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की पूर्ति सबसे अच्छी होगी।

***

47. (iv) मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को इस निर्णय के पहले भाग में बताए अनुसार प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व, जीवित दावे का अस्तित्व या अन्यथा, उसकी शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तों का अस्तित्व और मध्यस्थ या मध्यस्थों की योग्यता पर विचार करना के अनुरोध पर विचार करना उसका अपना अधिकार क्षेत्र होगा।"

28. उक्त अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद, हमें टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर), रेवा इलेक्ट्रिकल कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) और एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) में कही गई बातों के विपरीत कानून में कोई स्थिति नहीं मिली।

29. इसी तरह, क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) पर की गई निर्भरता भी किसी भी तरह से लिखित रूप में दर्ज किए गए मूल लेनदेन में स्टैन्ड-

अलोन मध्यस्थता खंड से संबंधित कानूनी स्थिति को खारिज नहीं करती है। अतः उक्त निर्णय को संदर्भित करने में हमें कोई उपयोगी प्रयोजन नजर नहीं आता।

30. इस प्रकार पक्षों के बीच कानूनी लेनदेन में मध्यस्थता समझौते के विशेष संदर्भ में मध्यस्थता से संबंधित स्टैंड अलोन समझौते के बारे में कानूनी स्थिति का पता लगाने के बाद, जब हम एमओयू के खंड 27 का उल्लेख करते हैं, तो हम यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या उक्त खंड निर्धारित सिद्धांतों को संतुष्ट करता है और अकेले मध्यस्थता समझौते पर लागू होता है। जब हम खंड 27 का उल्लेख करते हैं, तो हम पाते हैं कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद या मतभेद से संबंधित द्विपक्षीय स्तर पर कोई सौहार्दपूर्ण समाधान विफल होने की स्थिति में, जैसा कि एमओयू के खंड 26 में निहित है, तो इस तरह एमओयू से संबंधित या उत्पन्न होने वाले अनसुलझे विवाद या मतभेद, इसके कार्यान्वयन का उल्लंघन या समाप्ति, जिसमें एमओयू की किसी भी शर्त की व्याख्या के संबंध में कोई भी अंतर या विवाद शामिल है, अपीलकर्ता और प्रतिवादी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के लिए संदर्भित है। इसलिए, इस सवाल या इस तथ्य के बावजूद कि क्या एमओयू एक पूर्ण समझौते में परिणत हुआ, किसी भी शर्त को पूरा न करने या किसी भी पक्ष द्वारा एमओयू के दूसरे खंड में निर्धारित किसी भी आवश्यकता के अनुपालन में विफलता को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता और प्रतिवादी द्वारा खंड 27 के तहत पक्षों के बीच ऐसे विवादों को आम सहमति से एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजने के लिए विशिष्ट समझौता किया गया है। इसलिए, जब संदर्भ देने के लिए पक्षों के बीच आम सहमति नहीं बनी, तो अंततः यह दोनों पक्षों में से किसी एक के लिए अधिनियम की धारा 11 को लागू करने और मध्यस्थता के लिए विवाद के संदर्भ की मांग करने के लिए खुला होगा।

31. मौजूदा मामले में, जैसा कि हमने पहले नोट किया है, 17.8.2007 को एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रतिवादी के निदेशक मंडल ने 29.10.2007 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एमओयू के लिए अपनी मंजूरी व्यक्त की गई,

हालाँकि, शर्तों में संशोधन के अधीन। इसके बाद 17.12.2007 से 10.03.2010 तक पक्षों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान हुआ। 18.03.2010 को प्रतिवादी का एक अनुवर्ती बोर्ड प्रस्ताव था जिसमें कहा गया था कि बोर्ड ने निर्णय लिया कि वह राज्य सरकार की खनिज नीति में बदलाव के कारण प्रस्तावित एमओयू की वैधता को बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। हालाँकि, 26.07.2010 को, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि समानता बनाए रखने के लिए, 17.8.2007 के एमओयू के नियमों और शर्तों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को सूचित किया गया था, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी और इस तरह की मंजूरी मिलने पर, एक नया एमओयू निष्पादित किया जा सकता है। इसके बाद, दिनांक 25.4.2011 को संचार द्वारा, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि उसने एमओयू के विभिन्न नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता के संबंध में अपीलकर्ता की ओर से गलती का आरोप लगाते हुए दिनांक 17.8.2007 के एमओयू को तुरंत रद्द करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, 17.8.2007 और 25.4.2011 के बीच घटित घटनाओं के उपरोक्त अनुक्रम से, यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष एमओयू में निहित विभिन्न नियमों और शर्तों के संदर्भ में भिन्न थे और परिणामस्वरूप, एमओयू के खंड 26 में निर्दिष्ट अनुसार पहली बार में सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश करने का दोनों पक्षों में से प्रत्येक को पूरा अधिकार था।

32. हमें रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को संबोधित अपने पत्र दिनांक 11.07.2011 में द्विपक्षीय स्तर पर विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की इच्छा व्यक्त की थी। चूँकि प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, अपीलकर्ता ने 07.12.2012 को एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एमओयू के खंड 27 को लागू करके एक कानूनी नोटिस भेजा और एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम भी सुझाया और प्रतिवादी की सहमति मांगी। कानूनी नोटिस में, अपीलकर्ता ने विशेष रूप से सूचित किया कि यदि प्रतिवादी नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने में विफल रहता है, तो उसके पास

अधिनियम की धारा 11 के तहत उच्च न्यायालय में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। प्रतिवादी ने वकील के नोटिस पर दिनांक 04.01.2013 को अपने उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया कि वह संदर्भ के लिए सहमत होने के लिए इच्छुक नहीं है, अपीलकर्ता के पास अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय का रुख करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

33. उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए और चूँकि हम आश्वस्त हैं कि खंड 27 दिनांक 17.8.2007 के एमओयू में निहित एक वैध मध्यस्थता समझौता है, अपीलकर्ता उक्त समझौते को लागू करने और मध्यस्थ के संदर्भ की तलाश करने का पूरी तरह से हकदार था।

34. हमारे उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में, हम मानते हैं कि विद्वान न्यायाधीश एमओयू में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में कानूनी स्थिति को समझने में विफल रहे हैं, संयुक्त उद्यम के लिए एमओयू में निहित विभिन्न नियमों और शर्तों के संबंध में पूर्ण समझौते तक पहुंचने में पक्षों की विफलता के बावजूद, विद्वान न्यायाधीश का उक्त निष्कर्ष और निर्णय रद्द किये जाने योग्य है और तदनुसार रद्द किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी ने अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की है और इस प्रकार पार्टियां सहमत प्रक्रिया के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहीं, इसलिए इस न्यायालय के लिए मध्यस्थ नियुक्त करना आवश्यक है। इसलिए, इस अपील में दिए गए फैसले को रद्द करते हुए, हम पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय सुश्री रेखा मनहरलाल दोशित, निवासी सी-5, 402, देव संगम फ्लैट, गुअर्टगाम रोड, गांधी नगर के पास, गुजरात को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों को ऐसे नियमों और शर्तों पर निपटाने के लिए जिन्हें एकमात्र मध्यस्थ योग्य और उचित समझते है। निस्संदेह, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ पक्षों के संबंधित दावों के संबंध में इस

आदेश में व्यक्त किसी भी प्रथम दृष्टया राय से प्रभावित हुए बिना, एमओयू के तहत पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का फैसला करेंगे।

35. रजिस्ट्री को इस आदेश को एकमात्र मध्यस्थ को सूचित करने का निर्देश दिया गया है ताकि वह संदर्भ में प्रवेश कर सके और मामले को यथासंभव शीघ्र तय कर सके।

उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।